

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3546

जिसका उत्तर 24 मार्च, 2022 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन

3546. श्री जयंत सिन्हा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
- (ख) देश में मिशन के चरण 1 और 2 के तहत राज्य-वार कितने स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार ने पारंपरिक मीटरों की तुलना में स्मार्ट मीटर के लाभों का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार द्वारा भारत में स्मार्ट ग्रिड गतिविधियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाने और निगरानी करने के लिए वर्ष 2015 में राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) की स्थापना की गई थी। स्मार्ट ग्रिडों का प्राथमिक उद्देश्य विद्युत के नेटवर्क की विश्वसनीयता में सुधार करना और वितरित उत्पादन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा इनपुट्स को ग्रिड अनुगामी बनाना है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटरों के साथ बढ़ी हुई दक्षताओं से उपभोक्ता अपनी विद्युत खपत का बेहतर तरीके से प्रबंध करने में सक्षम होते हैं और उन्हें अपने बिल कम करने में सहायता मिलती है। इसके साथ-साथ, एनएसजीएम में स्मार्ट ग्रिडों के क्षेत्रों में वितरण क्षेत्र के कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण शुरुआतों की परिकल्पना भी की गई है।

(ख) : दिनांक 11.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, एनएसजीएम के अंतर्गत संस्थापित स्मार्ट मीटरों सहित, पूरे देश में अब तक, 40,19,755 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनके ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : मैसर्स क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) द्वारा आईआईटी, कानपुर में स्मार्ट सिटी पायलट और स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर (एसजीकेसी), मानेसर सहित स्मार्ट ग्रिड प्रायोगिक परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किया गया था और यह देखा गया है कि ज्यादातर डिस्कॉमों/यूटीलिटियों में एटीएंडसी हानियों को कम करने में की जा रही प्रगति से पर्याप्त उपलब्धि हासिल हुई है।

बिहार में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा बड़े पैमाने पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की संस्थापना के बाद संग्रहण में 20% तक का सुधार हुआ है।

लोक सभा में दिनांक 24.03.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3546 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य-वार स्मार्ट मीटर की संस्थापना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	संस्थापित स्मार्ट मीटर
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	74,900
2.	आंध्र प्रदेश	2,000
3.	असम	2,30,612
4.	बिहार	6,27,857
5.	चंडीगढ़	22,463
6.	दिल्ली	2,58,444
7.	गुजरात	23,760
8.	हरियाणा	4,15,390
9.	हिमाचल प्रदेश	77,047
10.	जम्मू एवं कश्मीर	37,650
11.	झारखंड	0
12.	कर्नाटक	20,916
13.	केरल	805
14.	मध्य प्रदेश	2,43,313
15.	ओडिशा	4,500
16.	पुदुचेरी	30,568
17.	पंजाब	88,107
18.	राजस्थान	5,41,618
19.	तमिलनाडु	98,320
20.	त्रिपुरा	43,081
21.	तेलंगाना	8,882
22.	उत्तर प्रदेश	11,54,358
23.	पश्चिम बंगाल	15,164
कुल		40,19,755

स्रोत: एनपीएमयू
